जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 335 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 27 जून, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

अक्टूबर-नवम्बर में प्रस्तावित हैं, बिहार एसैम्बली के चुनाव

243 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में भाजपा को घटते हुए ''वोट शेयर'' का सामना करना पड़ेगा

- 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा बारह सीटें जीती थी, पर, भाजपा का ''वोट शेयर'' 2019 के चुनाव के मुकाबले घटा था तथा सीटें भी कम आयी थीं।
- पर, फरवरी 2025 ''मूड ऑफ नैशन'' सर्वे में यह संभावना सामने आई थी कि एनडीए बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 33-35 सीटों पर विजयी हो सकता है तथा एनडीए का वोट शेयर 52 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।
- भाजपा बड़े आक्रामक तरीके से 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। अपना संगठनात्मक ढाँचा मजबूत कर रही है तथा जातिगत समीकरणों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से जातिगत नेतृत्व ढूंढ-ढूंढ कर, जातिगत नेताओं को चयनित करके उन्हें पनपा रही है। उदाहरण के लिए, सम्राट चौधरी (ओबीसी नेता) को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है।
- पर, प्र.मंत्री के, जून माह के मध्य में बिहार के किये गये सघन दौरे व बिहार को लगभग 10,000 करोड़ की सौगातें देने के बावजूद भी पार्टी के गठबंधन में आतंरिक मतभेदों के कारण भय है कि पार्टी का वोट शेयर घटेगा। शायद इसीलिए भाजपा ने नीतीश की पार्टी से सीटों के बंटवारे पर समझौता सा कर लिया है, पर, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी से बात नहीं की है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे हैं, जहाँ 243 सीटों पर मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) घटते वोट शेयर के संकट का सामना कर रही है।

भाजपा ने बिहार में चुनावी रणनीति के तहत रोहन गुप्ता के नेतृत्व में एक वॉर रूम बनाया है और विशेष ज़िला टीमें गठित की हैं, जो दिवाली-छठ के समय घर लौटने वाले प्रवासियों के साथ संवाद करेंगी।

एनडीए ने सीटों के बंटवारे की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हम पार्टी के जीतन राम मांझी से इस पर सलाह-मशविरा नहीं किया गया।

ओबीसी नेता सम्राट चौधरी को भाजपा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि जदयू के नीतीश कुमार को काउन्टर किया जा सके और प्रमुख जातिगत वोट बैंक को साधा जा सके।

26 फरवरी को, नीतीश कुमार की कैबिनेट में भाजपा के 7 विधायकों को शामिल किया गया, जिससे भाजपा को चुनाव से पहले राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिली।

2024 के आम चुनावों में भाजपा ने बिहार की 17 में से 12 सीटें जीतीं, लेकिन 2019 की तुलना में सीटें और वोट शेयर दोनों में गिरावट दर्ज की गई। एनडीए का लक्ष्य विधानसभा चुनावों में 220-225 सीटें जीतना है।

फरवरी 2025 के ''मूड ऑफ़ द नेशन'' सर्वे के अनुसार, एनडीए को बिहार की 40 में से 33-35 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, और वोट शेयर लगभग 52 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।

मोदी ने जून के मध्य में सीवान और जसौली का दौरा किया, जहाँ 9,519

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं-सीजेआई गवई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन उनके अनुसार संविधान सर्वोपरि है। मुख्य न्यायाधीश बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित अपने सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और लोकतंत्र के तीनों स्तंभ (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) उसके अधीन काम करते हैं।

- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने अमरावती में एक सम्मान समारोह में कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर, मूल स्वरूप को नहीं बदल सकती।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा, जो बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल सरकार के खिलाफ फैसले देने से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं बन जाता।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने डिजिटल मैसेजों की झड़ी लगाई

जैसा कि विदित ही है, अयातुल्ला लगभग एक सप्ताह से जनता की आँखों से ओझल हैं

- हालाँकि, ईरान सरकार उनकी अनुपस्थिति का कारण सुरक्षा के लिए किये गये कड़े बंदोबस्त को बता रहे हैं। इन सूत्रों का कहना है कि इज़रायल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू ने, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सार्वजनिक रूप से कहा है कि इज़रायल, अयातुल्ला को ''टारगैट'' कर सकता है, हालाँकि, अमेरिका ने इस संभावना को अंजाम नहीं देने की सलाह दी है।
- दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि अयातुल्ला ने स्वयम् दो वर्ष पहले उच्चस्तरीय धार्मिक नेताओं की एक समिति गठित की थी, जो उनके उत्तराधिकारी का चयन करे तथा उस समिति ने जोर-शोर से अपना काम शुरु कर दिया है।
- ईरान की सुरक्षा से सम्बद्ध एक टॉप अफसर ने ईरान की समाचार एजेंसी को बताया कि अयातुल्ला इस्लामिक गार्ड की विशेष टुकड़ी ''वली-ये-अम्र'' की सुरक्षा में हैं तथा उनसे व उनके परिवार से ईरान के वरिष्ठतम अधिकारी भी सीधा सम्पर्क नहीं कर सकते हैं। इज़रायल के 13 जून के अटैक, जिसमें ईरान के शीर्षस्थ आर्मी कमांडर व न्यूक्लियर साइंटिस्ट टारगैट करके मारे गये थे, को देखते हुए ईरान अब अपने सुप्रीम कमांडर के बारे में कुछ रिस्क लेने को तैयार नहीं है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अपनी अचानक और अस्पष्ट गुमशुदगी की अफवाहों पर ''एक्स'' के जरिए विराम लगाया है, जिससे एक नई बहस शुरु हो गई है।

ईरान, जिसने अमेरिकी और इज़रायली हवाई हमलों का सफलतापूर्वक जवाब देते हुए तेल अवीव की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी, अब अभूतपूर्व सैन्य वृद्धि और आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। लेकिन तेहरान शासन को सबसे ज्यादा परेशान किया, पश्चिमी मीडिया द्वारा अली खामनेई की अचानक और अस्पष्टीकृत गुमशुदगी के बारे में चल रही अटकलों ने।

86-वर्षीय नेता, जो इस्लामिक गणराज्य में सर्वोच्च अधिकार रखते हैं, पिछले एक हफ्ते से सार्वजनिक रूप से न तो कहीं दिखाई दिए और न उनकी आवाज़ सुनाई दी। हालांकि तेहरान स्थित सूत्रों का कहना है कि यह सब उनके जीवन की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इज़रायल दोनों ही ईरान में शासन परिवर्तन के लिए लालायित थे।

उनकी चुप्पी ने अफवाहों, चिंताओं और बेचैनी को जन्म दिया है, जो न केवल ईरान में, बल्कि बाहर भी महसूस हो रही है, जैसा कि पश्चिमी मीडिया लगातार कह रहा है।

खामनेई सबकी पहुँच और नज़र से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगले सप्ताह ईरान से वार्ता करेगा अमेरिका, पर वार्ता में समझौता हो यह जरुरी नहीं'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया कि ईरान को परमाणु महत्वाकांक्षा से पीछे हटने को राजी करना अब अमेरिका की प्राथमिकता नहीं है

- ट्रंप ने जोरदार अंदाज में यह दावा दोहराया कि अमेरिकन हमलों में ईरान की परमाणु सुविधाएँ नष्ट हो गई हैं, खासकर यूरेनियम संवर्धन की सुविधा।
- अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबिओ ने सैटलाइट तस्वीरें जारी कीं, जिनमें ईरान के परमाणु केन्द्रों में भारी तबाही दिख रही थी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले सप्ताह ईरान से बातचीत करेंगे, जबकि ईरान और इज़रायल के बीच संघर्षविराम दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस बातचीत का प्रारूप क्या होगा तथा क्या यह बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी प्रकार की रोक लगाने या उसकी सीमा तय करने के बारे में होगी।

'नाटो' सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ वार्ताओं का किसी भी समझौते पर पहुंचना जरुरी है। ट्रंप यह संकेत दे रहे थे कि ईरान को परमाणु महत्वाकांक्षा त्यागने के लिए राजी करना अब प्राथमिकता नहीं रही।

ट्रंप ने उस प्रारंभिक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को भी खारिज किया, जो मंगलवार को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों ने सिर्फ कुछ महीनों के लिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पीछे धकेला है।

ट्रंप ने दोहराया कि इन हमलों ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जनता जानती है, कुछ लोग कुर्सी के लिए कितना गिर सकते हैं'

जोधपुर/जयपुर, 26 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ''जिसकी कभी फटी ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग जनता के दुख-दर्द से कभी जुड़े ही नहीं, उन्हें आम जन की पीड़ा का वास्तविक अनुभव कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलाह दी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्वयं को आईने में देखना चाहिए और जनता से भी ईमानदारी से यह प्रश्न करना चाहिए कि उनके शासनकाल में जनता के साथ कितना कुठाराघात और अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश की जागरूक जनता भली-भांति जानती है कि कुछ लोग सत्ता की कुर्सी के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। कुर्सी के मोह में वे कितने गिर सकते हैं, यह अब किसी से छुपा नहीं है।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार किया।

'नैशनल टैस्टिंग एजेंसी असल में नैशनल करप्शन एजेंसी बन गई है'

कांग्रेस ने नीट परीक्षा के फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया

- कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोपी को जमानत मिलने का मुद्दा उठाया।
- कन्हैया कुमार ने कहा कि गत वर्ष भी नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। एनटीए के अधिकारियों पर इसके लिए कार्यवाही होनी चाहिए थी, पर, सरकार इन्हें बचा रही है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य, एन.एस.यू.आई. के प्रभारी तथा एन.एस.यू.आई. अध्यक्ष ने गुरुवार को नीट परीक्षा के आयोजन पर सवाल उठाए और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन.टी.ए.) को ''नेशनल करप्शन एजेंसी'' करार दिया।

ए.आई.सी.सी. के नए मुख्यालय, इंदिरा भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाराष्ट्र में सी.बी.आई. द्वारा दर्ज की गई एक नई एफ.आई.आर. का हवाला दिया, जिसमें आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया।

उन्होंने कहा कि एन.टी.ए. पर पिछले साल भी डेटा लीक के मामले में अनियमितताओं का आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संरक्षण देने के बजाय एन.टी.ए. के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और एन.टी.ए. के कामकाज की गहराई से जांच होनी चाहिए।

एन.एस.यू.आई. के ए.आई.सी.सी. इन्चार्ज कन्हैया कुमार ने कहा कि नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर उनकी पार्टी ने नहीं, बल्कि सी.बी.आई. ने सवाल उठाया है। दो लोगों को जमानत मिल गई है जबकि तीन अभी भी फरार हैं।

सी.बी.आई. ने महाराष्ट्र में एफ.आई.आर. दर्ज की है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीन लोग फरार हैं। जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत मिल गई है और ये गिरफ्तारियां भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत की गई हैं। इससे तीन अहम सवाल उठते हैं:

पहला, सी.बी.आई. कह रही है कि इसमें किसी भी एन.टी.ए. अधिकारी के लिप्त होने की संभावना नहीं है। सवाल यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी लिप्त नहीं है, तो फिर एफ.आई.आर. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत क्यों दर्ज की गई?

दूसरा, जब तीन लोग फरार हैं तो दो लोगों को जमानत कैसे मिल गई? और तीसरा, छात्रों के माता-पिता द्वारा दिए गए विवरण, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं, उन्हें देखकर क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी अनियमितता किसी वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता के बिना हो सकती है?

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन देश में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिस पर सवालिया निशान न हो। ऐसा कोई साल नहीं जाता, ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहाँ प्रश्नपत्र लीक नहीं हो रहे हैं।

कन्हैया कुमार ने कहा, सवाल यह है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना है। चाहे वह परीक्षा के नाम पर वीडियो बनाना हो या हादसा होने पर वीडियो बनाना, उन्हें सिर्फ रील्स बनाने में दिलचस्पी है।

एक्सिओम -4 अन्तर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से कनैक्ट हुआ

फ्लोरिडा, 26 जून। एक्सिओम-4 मिशन का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से जुड़ गया और इसके साथ ही, भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। वह आईएसएस में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गये।

- इसी के साथ भारतीय वायु सेना के कैप्टन शुभांशु अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

भारतीय अंतरिक्ष आकांक्षाओं के लिए एक बड़ी छलांग लगाते हुए भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज इतिहास में तब दर्ज हो गए जब ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत व अमेरिका में ताबड़तोड़ बातचीत चल रही है, ''ट्रेड-डील'' फाइनल करने के लिए

सबसे बड़ी रुकावट आ रही है, ''फार्म प्रोडक्ट्स'' (कृषि उत्पाद) के व्यापार में

- अमेरिका, अपने किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देता है। ''एनवायरमैंट प्रोटैक्शन'' (पर्यावरणीय सुरक्षा) आदि के नाम पर। इस सब्सिडी के कारण, अमेरिका के किसान अपना माल बहुत ही सस्ते दामों पर बेचता है। भारत इस सब्सिडी का मुकाबला नहीं कर सकता और उसे बाजार से उखड़ने का डर है, अमेरिकी माल के सामने।
- इसके अलावा, अमेरिका, अन्य देशों में उसके द्वारा विकसित जैनैटिकली मॉडिफाइड (जी.एम.) फसलें बेचना चाहता है, जिसे अन्य देशों के किसान सावधानी से परीक्षण किये बगैर स्वीकार नहीं करना चाहते।
- जापान ने तो व्यापार पर बातचीत करने से इंकार कर दिया था, जब अमेरिका ने अपना चावल उन पर थोपना चाहा था। जापान का तर्क था कि जापानवासी जापान में पैदा हुए ''स्टिकी'' चावल ही खाते हैं, उन्हें दूसरा चावल भाता ही नहीं।
- हालाँकि, 5 जुलाई से पहले भारत, अमेरिका से व्यापारिक समझौता कर लेना चाहता है, क्योंकि नहीं तो भारत पर भारी ''टैरिफ'' लगने की धमकी है।
- हालाँकि, कोई भी देश, कनपटी पर बंदूक लगाकर व्यापारिक सौदेबाजी बर्दाश्त करके अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहेगा।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। जैसा कि पहले तय हुआ था, एक ट्रेड टीम वर्तमान में अमेरिका का दौरा कर रही है, ताकि दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक समझौते के विवरण को 5 जुलाई की समयसीमा से पहले अंतिम रूप दिया जा सके, जब तथाकथित पारस्परिक शुल्क लागू हो जाएंगे।

हालाँकि वार्ताएँ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि उत्पादों के व्यापार में, गंभीर मतभेद उभर कर आए हैं।

किसी भी व्यापार वार्ता में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ी बाधा रहा है, भले ही राष्ट्रीय आय में इसका बहुत बड़ा योगदान न हो। इसका कारण यह है कि कृषि से जुड़े मुद्दे अत्यंत संवेदनशील और राजनीतिक रूप से बहुत ही नाज़ुक होते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में, अमेरिका की भारतीय कृषि बाजार में पहुँच की माँग ही सबसे बड़ी अड़चन बन रही है। अमेरिका मक्का, सोया, गेहूं जैसे उत्पादों का एक विशाल उत्पादक है। भारत भी इन उत्पादों का बड़ा उत्पादक है, लेकिन देश में माँग भी बहुत अधिक है।

दो प्रमुख मुद्दे हैं, पहला है, कृषि सब्सिडी। अमेरिका अपने किसानों को इतनी भारी सब्सिडी देता है, जिसका मुकाबला भारत नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अमेरिका के कपास उत्पादकों को 100 अरब डॉलर की सब्सिडी मिल रही है, जो अमेरिकी कृषि का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसी वजह से डब्ल्यु.टी.ओ. में अमेरिका और अफ्रीकी देशों के बीच बातचीत रुक गई थी। पर्यावरण संरक्षण और अन्य उपायों के नाम पर किसानों को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे वस्तुतः लागत से कम कीमत पर माल बेचकर अमेरिकी उत्पादक बाज़ार पर कब्ज़ा कर सकते हैं।

दूसरा मसला है, अमेरिका में बड़ी संख्या में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें उगाई जाती हैं। ऐसे बीजों का प्रसार और सामान्य खेती में उनका घुसपैठ करना भारत की पारंपरिक फसलों के लिए विनाशकारी हो सकता है। इससे देश की स्थानीय किस्मों की जैव विविधता को खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसे बीजों को किसी नए पर्यावरण में अपनाने और उपभोग से पहले उचित सावधानी बरतनी आवश्यक है। इस संदर्भ में संरक्षण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

345 राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द

नयी दिल्ली, 26 जून। चुनाव आयोग ने ऐसे 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान कर उनको सूची से हटाने का काम शुरु कर दिया है जो पिछले छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने मिलकर 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दायरे में वे सभी राजनीतिक दल होंगे, जो 2019 से कहीं भी सक्रिय नहीं हैं। ये सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त दल देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं। आयोग ने कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि वर्तमान में आयोग के पास 2,800 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दल हैं।

- चुनाव आयोग ने कहा कि इन दलों ने 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा है।